भारतीय जनता पार्टी
राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक
7–8–9 सितम्बर
देहरादून (उत्तरांचल)

अध्यक्षीय भाषण

बंधुओं,

पवित्र धाम बदरी–केदारनाथ की पुण्य भूमि और गंगा–यमुना के पावन उद्गम की स्थली उत्तरांचल चिरंतन देवभूमि है। यह सुखद संयोग है कि हम यहां एकत्र हैं।

विगत राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हम दिल्ली में मिले थे। इन तीन महीनों की घटनाओं से देश के राजनीतिक पटल पर कई चिंताजनक दृश्य उभरे हैं। जो किसी भी राष्ट्रभक्त के मनमें अनेक प्रश्न उत्पन्न करते हैं। मुम्बई के बम धमाकों ने भारत की सुरक्षा को एक बड़ी चुनौती दी है। अलगाव की मानसिकता लगातार पैर पसार रही है। अतः राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना व्यावहारिक और वैचारिक दोनों दृष्टिओं से आवश्यक है। आज देश प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की 150वीं और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे–मातरम् के अंगीकार होने की सौवीं वर्षगांठ मना रहा है। इसी वर्ष शहीद चन्द्रशेखर आजाद की जन्मशताब्दी भी है। किसी भी देश के लिए ऐसा अवसर राष्ट्रीयता की भावना के संचार का प्रतीक होना चाहिए। पर हमें दुःख है कि वर्तमान यूपीए सरकार इस ऐतिहासिक स्मरण के अवसर पर भी राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ करने के स्थान पर अपने वोट बैंक को सुदृढ़ करने में अधिक रुचि ले रही है। इतना ही नहीं, वह वंदे–मातरम् जिसे गाते हुए भारत की आजादी के अनेक शहीद फांसी के फंदे पर झूल गए, जिसे गाकर भारत की स्वतंत्रता अस्तित्व में आयी, उसी वंदे–मातरम् का आज स्वतंत्र भारत में गाया जाना सुनिश्चित करने का साहस सरकार में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि शहीदों के अमर उद्घोष वंदे–मातरम् को वर्तमान यूपीए सरकार वोट बैंक की बलि वेदी पर शहीद करने पर आमादा है।

इससे भी आगे जाकर अतीत के हमारे वे गौरवशाली प्रसंग जिनके कारण हमारी संस्कृति सतत् जीवंत रही है, उस पर भी एनसीईआरटी और इग्नू के पुस्तकों के माध्यम से आघात किया जा रहा है। भावी पीढ़ियों को संस्कृति और राष्ट्रीयता के इन तत्वों से विमुख करना उनके साथ अन्याय है। केवल सरकार चलाने के लिए राष्ट्र के अतीत और भविष्य दोनों के साथ खिलवाड़। बंधुओं, यह राजनीति के पतन का नया आयाम है। आज देश में वामपंथियों की अनाधिकार चेष्टा एवं कांग्रेस के अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की पराकाष्ठा का तांडव देखने को मिल रहा है।

यूपीए सरकार के ऐसे कदमों की हम घोर भर्त्सना करते हैं। साथ ही चेतावनी भी देना चाहते हैं कि राष्ट्रगीत 'वन्देमातरम्' और अतीत के स्वाभिमान की गौरवशाली गाथाओं से छेड़छाड़ करने का यूपीए सरकार का स्वप्न हम कभी पूरा नहीं होने देगें।

यूपीए शासन में देश की यही नियति है। हमें तो स्वयं को सक्षम और मानसिक रूप से तैयार रखने की आवश्यकता है। हमें आने वाले दिनों में कठिनतम् जन परीक्षा के दौर से गुजरना होगा। यूपीए की हालत निरंतर पतली होती जा रही है। उनके आपसी घटकों के दरकने का दौर शुरू हो गया हैं। आपस का वाद–विवाद और गहराने लगा है। वामपंथियों ने साफ शब्दों में कह दिया है कि आने वाले दिनों में यदि केन्द्र में बेहतर विकल्प मिला तो हम कांग्रेस से समर्थन वापिस ले लेंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री का यह कहना कि वामपंथियों को धमकी देने के बजाए समर्थन वापिस ले लेना चाहिए। यह बातें स्वयं में यूपीए घटकों की कलह अंदरूनी कहानी कह रही है। यूपीए गठबंधन के बारे में हम सभी लोग प्रारम्भ से ही कह रहे हैं कि यह अप्राकृतिक गठबंधन है। भाजपा सत्ता में नहीं आए, इस विरोध पर यूपीए गठबंधन का जन्म हुआ। मुझे साफतौर पर लग रहा है कि केन्द्र की यूपीए सरकार असमय गिरेगी और देश को पुनः मध्यावधि चुनाव के दौर से गुजरना होगा।

पिछले दो साल से देशभर में राजनैतिक दिशाहीनता का चिंताजनक वातावरण बना हुआ है। केन्द्र की सरकार के घटक और सहयोगी ही नहीं मंत्री भी पूरी तरह निरंकुश हो चुके हैं। सत्ता के एक नहीं अनेक केन्द्र बने हुए हैं। ऐसे में शासन–प्रशासन की तत्परता और विकास की योजनाओं की गतिशीलता पूरी तरह खो चुकी हैं। केन्द्र सरकार किसी भी मसले पर ईमानदार साबित नहीं हो रही हैं। मसला महंगाई का हो, आतंकवाद का हो, किसानों की आत्महत्या का हो, न्यूक्लियर डील का हो, पाठक समिति की रिपोर्ट का हो, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन का हो, केन्द्र राज्य संबंध का हो या फिर विदेश नीति का हो या फिर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण का हो, या फिर बेरोजगारी का हो। यह सब सरकार की अदूरदर्शिता अक्षमता और अकर्मण्यता के उदाहरण बन चुके हैं।

विगत तीन माह के कार्यक्रम

हमने पिछले तीन महीनों में महंगाई से त्रस्त आम नागरिकों की लड़ाई संसद से लेकर सड़कों तक लड़ी है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मा. आडवाणी जी, सहित देश के सभी राज्यों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारियां देकर केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर आगाह किया। लेकिन केन्द्र सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वहीं जम्मू–काश्मीर से हमने आतंकवाद के विरूद्ध धरना, प्रदर्शन का कार्यक्रम लिया और फिर उसे और आगे बढ़ाकर देशभर में चलाया। किसानों की आत्महत्या को लेकर संघर्ष की एक लंबी योजना तैयार की गई है। हमारी महिला मोर्चा ने देशभर में महंगाई के विरूद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया और राज्यों में राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा। उसी तरह युवा मोर्चा ने आतंकवाद के विरूद्ध देशभर में मानव श्रृंखला बनाकर अपना विरोध जताया। संसद के मानसून सत्र में देश की सामयिक राष्ट्रीय समस्याओं को हमारे सांसदों ने बड़ी प्रबलता से उठाते हुए यूपीए सरकार को उनकी गलतियों का एहसास कराया। साथ ही आज देश का आम नागरिक जिन संकटों से गुजर रहा है, उस ओर भी यूपीए सरकार का ध्यान आकर्षित किया।

पिछले आठ–नौ माह में मेरा देश के 25–26 राज्यों में निरंतर किसी न किसी कार्यक्रमों, प्रदर्शनों, प्रदेश कार्यसमिति की बैठकों, किसान सम्मेलनों एवं कार्यकर्ता

सम्मेलनों के निमित्त जाना हुआ है। मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आम कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। वे यूपीए सरकार की गलत नीतियों का अपने–अपने स्तर पर जबर्दस्त विरोध कर रहे हैं। हम सभी को अपने कार्यकर्ताओं की अपने–अपने स्थान पर चिंता करना चाहिए। मुझे विश्वास है कि आप सभी लोग करते ही होंगे।

अनियंत्रित महंगाई

संप्रग सरकार जनविरोधी नीतियों की सरकार है। इस सरकार के शासनकाल में बढ़ती महंगाई से सब लोग त्राहि–त्राहि कर रहे हैं। अर्थशास्त्र के विद्वान प्रधानमंत्री जनता में विचित्र अर्थशास्त्र स्थापित कर रहे हैं। अमीर तो और अधिक अमीर हो रहे हैं और गरीब निरंतर गरीबी में ही जीवनयापन कर रहे हैं। यह विचित्र है कि एक तरफ हवाई जहाज का किराया, लक्जरी कार, ए.सी. आदि सस्ते हो रहे हैं तो दूसरी तरफ आम जरूरतों की चीजें महंगी हो रही हैं। दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं, चावल, दाल, गेहूं, सब्जी तेल जैसे खाद्य पदार्थों के दाम लगातार बढ़ाए जाने से अधिकांश लोगों के घर का बजट बिगड़ गया है। ऐसा लगता है कि संप्रग सरकार में आम लोगों की तरक्की संभव ही नहीं है। इससे भी आगे जाकर गैस, डीजल, पेट्रोल, सीमेंट, ईंट, रेत, बांस–बल्ली की कीमतों के साथ–साथ आवास ऋण पर निरन्तर बढ़ते ब्याज ने मध्यम वर्ग के लोगों का घर बनाने का सपना जो एनडीए के शासन में हकीकत होने लगा था उसे चकनाचूर दिया है। वहीं बीज और खाद की बढ़ती कीमतों से किसान आहत है। यूपीए शासन में कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय हो रहे हैं जो भारत की हजारों वर्ष पुरानी कृषि व्यवस्था का सारा स्वरूप बिगाड़ सकते हैं। सबसे शर्मनाक तो यह है कि सर्वहारा के हितों के स्वयंभू मसीहा वामपंथी दल केवल उत्तरदायित्त्व हीन सत्तासुख भोगने में लगे हैं। जनता की नजरों में संप्रग सरकार स्पष्ट रूप से नकारा साबित हो रही है। देश की जनता अब समझने लगी है कि कांग्रेस जब भी सत्ता में आयेगी तो महंगाई भी साथ लायेगी। देश की जनता स्पष्ट रूप से अनुभव कर रही है कि राजग के 6 वर्ष के शासनकाल में केवल इस सरकार की तुलना में नहीं बल्कि पिछली सभी सरकारों की तुलना में महंगाई सर्वाधिक नियंत्रित रही।

किसानों की आत्महत्या

दुःखद स्थिति है कि अन्नदाता किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। संप्रग सरकार की कृषि विरोधी नीतियों के चलते किसानों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, केरल के किसान अनेक समस्याओं से तंग आकर अपने को मौत के गले लगा रहे हैं। एक ओर किसानों पर कर्ज का ब्याज बढ़ रहा है तो दूसरी और लोडशेडिंग के कारण खेती करने के लिए उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस के किसानों से किए गए सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने वादा किया था कि हम किसानों को मुफ्त बिजली देंगे। इस आधार पर किसानों ने बहुत उम्मीद से कांग्रेस को अपना समर्थन किया। लेकिन कांग्रेस ने अपना चरित्र बदला नहीं और सत्ता प्राप्त करते ही किसानों को ठेंगा दिखा दिया। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विदर्भ के किसानों के लिए पैकेज की घोषणा की। उसके बाद भी किसानों की आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है। क्या केवल पैकेज की घोषणा कर देना ही सरकार का काम है? सरकार को

किसानों की समस्या को दूर करने के लिए व्यापक एवं दूरगामी प्रयास करने होंगे। किसान भारत की समाजिक जीवन का भी आधार है। किसानों को खुशहाल किए बिना देश तरक्की नहीं कर सकता। महानगरीय जीवन में आर्थिक विकास के नए आयाम प्रस्तुत करता हमारा विकास यूपीए सरकार में किसानों को इतना भी दे पा रहा कि वे आत्महत्या करने से रुक सकें। शायद अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री इसे समझने में पूरी तरह विफल रहे हैं।

भयावह बेरोजगारी

बढ़ती बेरोजगारी भारत के भविष्य के लिए चुनौती है। उदारीकरण और भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया अपनाने के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेराजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। बेरोजगारी के आंकड़े चिन्ताजनक है। 17 प्रतिशत ग्रेजुएट बेरोजगार है। यानी पढ़े लिखे शिक्षित युवा को भी रोजगार नहीं मिल रहे है। बेरोजगारी बढ़ने से देश में अनेक अन्य समस्याएं भी जन्म लेती है। असामाजिक तत्वों द्वारा बेरोजगारों को गुमराह करके उन्हें राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में धकेले जाने की संभावना भी बनी रहती है। संप्रग सरकार ने बहुत ही जोर–शोर से रोजगार गारंटी योजना लागू की थी। इसमें तमाम खामियां है, यथा इसमें शहरी बेरोजगारों के विषय में कोई स्पष्ट नीति नहीं है। 100 दिन के अतिरिक्त बाकी 265 दिन लोग क्या करेंगे? अभी भी इसके सही क्रियान्वयन के लिए तमाम आशंकाएं बनी हुई है। अनेक राज्यों में इसके दुरूपयोग के मामले सामने आए है। फिर भी इस योजना से जितना भी बेरोजगार युवकों का कल्याण संभव है उस प्रक्रिया में भी स्वयं सरकारों रिपोटों के अनुसार भाजपा शासित राज्य सर्वोच्च स्थान पर हैं। यह बेरोजगारी की समस्या के उन्मूलन के प्रति भाजपा की गम्भीरता का प्रमाण है।

संगठन के स्तर पर भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने बेरोजगारी जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण किया है। सर्वेक्षण के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमें सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर ध्यान देना होगा साथ ही हमारे देश के आधार कृषि क्षेत्र में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

देश की आर्थिक स्थिति

देश की अर्थव्यवस्था का विकास मंद पड़ता जा रहा है। कई क्षेत्रों में तो यह प्रतिगामी भी दिखाई पड़ रहा है। विनिवेश पर रोक लग गई है। दीवालिया कंपनियों को बेचते समय सरकार ने जो वादे किए थे। वे पूरे होते नजर नहीं आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में मूल्य नियंत्रण (प्राइज कन्ट्रोल) लागू होने से इस क्षेत्र के विकास की गति भी प्रभावित हुई है। मैंने कस्टम और एक्साइज डयूटी की दरों को और अधिक उपयुक्त बनाने की बात कही थी। केन्द्र सरकार ने निरन्तर बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों के बावजूद एक्साइज और कस्टम डयूटी में कमी नहीं की है। जिससे आम नागरिकों और तेल कंपनियों दोनों पर दबाव बढ़ रहा है। वर्ष 2003 में बने इलेक्ट्रिसिटी एक्ट को रद्द किए जाने से ऊर्जा क्षेत्र के विकास पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। कृषि उत्पादों को एक दूसरे स्थान ले जाने पर रोक लगाने के सरकार के निर्णय से भ्रष्टाचार और कालाबाजारी बढ़ने की संभावना है। ऐसा प्रतीत

होता है कि यह सरकार आर्थिक सुधार के विपरीत जाने वाले सुझावों को तत्काल मंजूर कर लेती है और आर्थिक सुधार की गति बढ़ाने वाले कदम उठाने का साहस नहीं जुटा पाती। इसी कारण से ऊर्जा अवस्थापना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) से लेकर पेट्रोलियम और कृषि तथा खाद्य पदार्थ तक के सभी क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव साफा दिखाई पड़ रहा है।

बढ़ता आतंकवाद

संप्रग सरकार की गलत नीतियों से आतंकवाद पूरे देश में विस्तार पा रहा है। गत दो वर्षों से आतंकवादी गतिविधियों में भयंकर तेजी आई है। जैश–ए मोहम्मद लश्करे तय्यबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन सभी राष्ट्रीय प्रतीकों को निशाना बना रहे है चाहे अयोध्या में रामजन्मभूमि पर हमला हो, दीपावली के मौके पर हमारी हमारी राजधानी दिल्ली पर, सांस्कृतिक केन्द्र काशी या फिर आर्थिक केन्द्र मुम्बई या आधुनिक भारत की पहचान के रूप में उभर रहे बैंगलोर पर हमला हो या राष्ट्रवाद के प्रतीक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केन्द्र पर हमले का प्रयास हो। अभी हाल ही में मुम्बई की लोकल ट्रेनों के साथ–साथ श्रीनगर में एक के बाद एक हुए बम विस्फोटों से पूरा देश दहल उठा। मुंबई की इस घटना में दौ सौ से अधिक लोगों की मौत हुई तथा सैंकड़ों लोग घायल हुए। सारे देश में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों का खून बहाकर भय और दहशत का माहौल बनाने का दुःसाहस किया हैं।

बढ़ता आतंकवाद हमारे देश के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेसनीत संप्रग सरकार आतंकवादियों के प्रति नरम रूख अपनाये हुए है। यह भी चिंता का विषय है कि हमारे पड़ोसी देश की धरती से आतंकवाद को समर्थन मिल रहा है। पिछले ही महीने संसद में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से बताया था कि पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में 52 आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। अमेरिका ने भी यह माना है। ऐसे में पाकिस्तानी राष्ट्रपति का बयान कि पाकिस्तान से आतंकवादी गतिविधियां संचालित नहीं होती, भारत के साथ धोखा है। भाजपा नेतृत्व वाली राजग सरकार ने आतंकवाद को कुचलने के लिए हर संभव प्रयास किए थे। आतंकवादी गतिविधियों पर उचित नियंत्रण रह सके इसलिए पोटा कानून बनाया गया था लेकिन संप्रग सरकार ने सबसे पहले पोटा कानून को हटाया, और इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। आतंकवाद के प्रति यूपीए सरकार का रवैया मात्र नरम ही नहीं रहा बल्कि उत्तरोत्तर समझौतावादी रहा है। पहले इस सरकार ने POTA हटाकर आतंकवादी शक्तियों को कानूनी रियायत दी फिर कांग्रेस और वामपंथियों ने केरल विधानसभा में कोयम्बटूर विस्फोट के मुख्य आरोपी अब्दुल नसीर मदनी की पेरोल पर रिहाई का प्रस्ताव पारित करके आतंकवादी ताकतों को संवैधानिक रियायत देने का शर्मनाक उदाहरण रखा और अब राष्ट्रगीत के मुद्दे पर कट्टरपंथी ताकतों के आगे नैतिक ओर वैचारिक समर्पण कर रही है। यह सोचने का विषय है कि क्या ऐसी नीतियों से देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रह पायेगी? क्या केन्द्र सरकार द्वारा अपनी राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए राष्ट्रहित की बलि चढ़ाना उचित है? भाजपा यह मानती है कि आतंकवाद व नक्सलवाद की समस्या कांग्रेस शासन की देन है। नक्सलवाद के प्रति कांग्रेस की नरम नीति देश की आतंरिक सुरक्षा

के लिए चुनौती बन गयी है। आंध्रप्रदेश के गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा नक्सलियों से मदद लेने के खतरनाक परिणाम सामने आयेंगे। आज देश की 17 फीसदी आबादी नक्सलवाद से पीड़ित है। यह भी चिंता का विषय है कि नक्सलवाद, जिहादी आतंकवाद, नेपाल के माओवादियों और आईएसआई के तार आपस में जुड़े हुए है। मैं नक्सलियों से कहना चाहता हूं कि हिंसा के लिए भारत में कोई जगह नहीं है। हिंसा, अन्ततः देश को अराजकता की ओर धकेलती है।

आतंकवाद के प्रति ऐसी नरम नीतियों के चलते ही आतंकवादियों के हौसलें इतने बढ़ गए हैं कि इस वर्ष 15 अगस्त पर आतंकवादी हमलों की आशंका के खौफनाक साये में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था।

भाजपा का मानना है कि पानी अब सिर से ऊपर हो रहा है। अब आतंकवादियों पर कड़े कानूनी शिकंजे की आवश्यकता है। अतः भाजपा यह मांग करती है कि सरकार आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए POTA पुनः लागू करे। यह विचार केवल विरोधी दल के रूप में हमारा नहीं है। बल्कि सड़क और ट्रेन में चलने वाले आम आदमी से लेकर वायुयान में चलने वाले खास आदमियों तक सभी देशवासियों के मन की यह भावना है।

प्राकृतिक आपदाओं से जूझने में यूपीए असफल

हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों अतिवर्षा के कारण अनेक राज्यों में बाढ़ ने सामान्य जनजीवन को तहस–नहस ही नहीं किया बल्कि उसमें सैंकड़ों लोगों की जानें भी गईं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। गुजरात, राजस्थान, म.प्र., छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आन्ध्रप्रदेश, कर्नाटक सहित उड़ीसा में भीषण बाढ़ से मात्र फसलों को ही नुकसान नहीं पहुंचा बल्कि लाखों लोग बेघर–बार हो गए। भाजपा एवं भाजपा गठबंधन द्वारा शासित राज्यों ने अपने स्तर पर जहां राहत कार्य किए वहीं केन्द्र सरकार से भी सहयाता की मांग की। मुझे यहां दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि केन्द्र की यूपीए सरकार ने भाजपा शासित राज्यों के साथ आर्थिक सहायता में भी भेदभाव किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं अनेक राज्य सूखे की चपेट में हैं, वहां पर भी केन्द्र सरकार मदद करने में पूरी तरह असफल है। हमारी प्रदेश ईकाई एवं जहां हम सरकार में हैं वहां के मुख्यमंत्रियों ने सरकार को प्राकृतिक आपदा से हुई स्थिति की पूरी जानकारी दी। सांसदों ने भी अपने–अपने राज्यों की बात लोकसभा में रखी और सरकार को बताया। बावजूद इसके केन्द्र की यूपीए सरकार सिर्फ आश्वासन देती रही और सहायता के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही करती रही। हम केन्द्र सरकार की इस कृत्य की कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं और उनसे मांग करते हैं कि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित राज्यों और वहां के नागरिकों के आंसू पोंछने में बिना किसी भेदभाव के आगे आए।

पाठक समिति की रिपोर्ट/जांच के नाम पर सच छुपाने का प्रयास

संप्रग सरकार की विश्वसनीयता और इरादे पर उस समय प्रश्नचिन्ह लग गया जब वोल्कर रिपोर्ट मामले की जांच के लिए गठित न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक प्राधिकरण की रिपोर्ट लीक हो गई। इससे केन्द्र सरकार संदेह के घेरे में आ जाती है

कि न्यायमूर्ति पाठक द्वारा प्रधानमंत्री को रिपोर्ट सौंपे जाने के कुछ ही मिनटों बाद मीडिया के पास रिपोर्ट के कुछ हिस्से कैसे पहुंच गए। जाहिर है ऐसा जानबूझ कर किया गया ताकि देश की जनता में संभ्रम की स्थिति निर्माण हो सके और कांग्रेस को पाक – साफ साबित किया जा सके। अभी भी इस मामले की पूरी सच्चाई सामने आना बाकी है। 'कांग्रेस' के नाम से जो वाऊचर थे, उससे तेल किसने उठाया और पैसे किसने लिए? इस मामले में सच को निगलने की साजिश की गई। भारतीय जनता पार्टी पूर्व से यह मांग करती रही है कि इस मामले में बतौर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी से पूछताछ क्यों नहीं की गई? वहीं श्रीमती सोनिया गांधी ने इस विषय पर आज तक चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी? पाठक समिति की रिपोर्ट ने इस मामले में एक नहीं अनेक प्रश्न खड़े कर दिए हैं।

परमाणु समझौता

भारत अमरीका परमाणु समझौता आज हर देशभक्त के मन में चिंता की लकीर खींच रहा हैं हमारी सरकार के समय में भी अमरीका से सामरिक सहयोग की बात चली थी। हमने नागरिक उपयोगिता के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा एवं उच्च तकनीक के क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता की थी। परन्तु वर्तमान समझौते जैसी शर्तें सामने आने पर उनको मानने से हमने स्पष्ट इंकार कर दिया था।

मैं नाभिकीय समझौते की तमाम शर्तों की व्याख्या करने में जुटी सरकार से पूछना चाहूंगा कि इन बातों से अलग हटकर मूल प्रश्न यह है कि क्या आज भारत को ऐसे किसी परमाणु समझौते की आवश्यकता भी थी। हमने आज तक अपना परमाणु कार्यक्रम स्वदेशी तकनीकि से चलाया है। अपनी प्रतिरक्षात्मक परमाणु क्षमता के विकास की संभावनाओं को कभी सीमित नहीं किया है। भारत में यूरेनियम का उचित भंडार है और थोरियम का सबसे बढ़ा भण्डार है। क्या इतना सब होने पर भी देश के लगभग दो तिहाई रियक्टरों को निरीक्षण सूची में स्वीकार कर लेना क्या उचित था? और एन.पी.टी. व सी.टी.बी.टी. की शर्तों से भी कुछ मायने में अनुचित कुछ शर्तों को स्वीकार करना क्या आवश्यक था? ऐसा कौन सा ऊर्जा संकट देश में था जो केवल इसी समझौते से पूरा हो सकता था?

पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटलजी ने गत वर्ष जुलाई में ही इस पर अपनी आपत्ति दर्ज की थी। तब से अब तक भाजपा ने इस विषय पर जो दबाव बनाया उसी के कारण सरकार को कई शर्तों पर अपना रुख बदलना पड़ा। परन्तु फिर भी हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। भाजपा यह मांग करती है कि इस समझौते को तब तक अन्तिम रूप न किया जाए जब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत को परमाणु अस्त्र की क्षमता वाले देश के रूप में मान्यता न दे दे।

पड़ोसी देश

हमारे पड़ोसी राष्ट्रों में पाकिस्तान तो लम्बे समय से हमारे विरुद्ध विध्वंसक गतिविधियों का केन्द्र रहा ही है। अब नेपाल में माओवादियों की बढ़ती ताकत और उस पर वामपंथियों का सहानुभूतिपूर्ण रवैया देश की सुरक्षा के भविष्य को और चुनौतीपूर्ण बना रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान पुनः सक्रिय हो रहा है। बांग्लादेश में जिहादी

आतंकवाद के नए केन्द्र उभर रहे हैं। श्रीलंका में LTTE और सरकार का संघर्ष तेज हो रहा है।

अभी हाल ही में पाकिस्तान सेना ने बूलच नेता नवाब अकबर खान बुगती की हत्या करके बलूचिस्तान में जिस संघर्ष को जन्म दिया है। वह और उग्र लेकर इस सारे क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर सकता है।

इन सारी परिस्थितियों में भारत के हितों के अनुरूप कोई उपयुक्त नीति भारत सरकार बनाने में असफल रही है। यदि यह कहा जाए कि सम्पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप अस्थिरता की ओर बढ़ रहा है और वर्तमान यूपीए सरकार भारत के भू–राजनैतिक हितों की रक्षा करने में अक्षम नजर आ रही है। तो यह अतिश्योक्ति न होगी।

महिला आरक्षण

महिलाओं के संसद में आरक्षण का प्रयास गंभीरता से आदरणीय अटलजी ने अपनी सरकार में प्रारम्भ किया था। कई तकनीकि कारणों से यह आज तक एक निश्चित स्वरूप नहीं ले सका। जिसमें सबसे बड़ी तकनीकि समस्या निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण है। भाजपा का यह मानना है कि महिला आरक्षण विधेयक तत्काल लाया जाना चाहिए यदि इसके लिए संसद में एक तिहाई सीटें बढ़ाने की आवश्यकता हो तो उस पर भी विचार करना चाहिए। बढ़ी हुई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती है। तेजी से विकसित होते देश में संसद में प्रतिनिधित्व एवं संख्या दोनों का विकास एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। हमें खुले दिमाग से इस पर विचार करना चाहिए। यदि सरकार इस विषय पर गंभीर है तो संसद के आगामी सत्र में महिला आरक्षण विधेयक लाए, हम उसका समथ्रन करेंगे।

अल्पसंख्यक तुष्टिकरण

कांग्रेस की राजनीति अल्पसंख्यक तुष्टिकरण पर ही आधारित है। उसे देशहित की कोई चिंता नहीं है। गत दो वर्षों में तो उसने तुष्टिकरण की सारी सीमाएं लांघ दी है। संविधान की अनदेखी करते हुए कांग्रेस की आंध्रप्रदेश की सरकार ने सरकारी नौकरियों में तथा कांग्रेसनीत संप्रग सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु मुस्लिम छात्रों को मजहबी आरक्षण देने का प्रयास किया। सेना में मुस्लिमों की गणना करवाने का भी प्रयास किया। केरल की विधानसभा में कोयम्बटूर बम विस्फोट के प्रमुख अभियुक्त अब्दुल मदनी को कारागार से मुक्त करने को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह सबसे निन्दनीय कृत्य है। इसी प्रकार कांग्रेस के अल्पसंख्यक प्रेम के साथ दलित विरोधी चेहरा उस समय उजागर हो गया जब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को आरक्षण से वंचित कर दिया।

शिक्षा में षडयंत्र

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में वामपंथियों और कांग्रेसियों ने मिलीभगत करके पाठ्यक्रमों को विकृत रूप में प्रस्तुत करके भारत में राष्ट्रवादी विचारों को कमजोर करने का कार्य किया। राजग सरकार के कार्यकाल में तत्कालीन मानव

संसाधन विकास मंत्री डा. मुरली मनोहर जोशी ने एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में शामिल तमाम अराष्ट्रीय बातों को देश के प्रबुद्ध शिक्षाविदों से अनुमोदन लेकर निकाल बाहर किया।

उस समय वामपंथी दलों और तथाकथित शिक्षाविदों ने इसे शिक्षा का भगवाकरण कहकर बहुत शोर मचाया लेकिन उच्चतम न्यायालय ने राजग सरकार द्वारा शैक्षिक पाठ्यक्रमों में किए गए बदलाव को सही ठहराया। अब जब केन्द्र में कांग्रेसी और वामपंथी एक साथ पुनः सत्तासीन है तो इन्होंने फिर एनसीईआरटी पाठ्यक्रमों में तमाम अराष्ट्रीय बातों को शामिल कर लिया है। गुरू तेगबहादुर, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे राष्ट्रीय नायकों के बारे में अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। हर राष्ट्र आनेवाली पीढ़ी को अपना गौरवशाली इतिहास पढ़ाता है। यह देश का दुर्भाग्य है कि राष्ट्र को नकारनेवाले दलों के हाथ में सत्ता होने के कारण राष्ट्रवाद आज तिरोहित है। हमारे आराध्य देवी–देवताओं, शिव, कृष्ण, पार्वती, काली, दुर्गा का चरित्र विकृत कर प्रस्तुत किया गया है। इनके बारे में ऐसी बातें पढ़ाई जा रही है जो उद्धृत करने में भी मुझे शर्म महसूस होती है। दूसरी ओर, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नक्सलवाद को बड़ी समस्या बताते हैं और नक्सलवादी कवियों की कविताएं विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है। क्या यह देश के नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं है? क्या शिक्षा में वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए? संसद में भाजपा सांसदों ने केन्द्र सरकार पर इस मुद्दे को लेकर जमकर प्रहार किया और इसी दबाव के चलते केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्री को इस पूरे मामले पर जांच समिति बनानी पड़ी। देशभर में आवाज गूंज रही है कि एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बदलो। सरकार को घुटने टेकने ही होंगे अन्यथा भाजपा देशभर में इस आंदोलन को और तेजी से आगे बढ़ाएगी। मैं इस अवसर पर शिक्षा बचाओ आंदोलन को भी बधाई देना चाहता हूं कि वे यूपीए सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे षडयंत्रों का पर्दाफाश जनजागरण, सेमिनार, प्रदर्शन के साथ–साथ न्यायालय के माध्यम से करने में जुटे हैं।

तेलंगाना

आंध्र प्रदेश में गत विधानसभा चुनाव–प्रचार के समय कांग्रेस ने राज्य की जनता से तेलंगाना राज्य निर्माण के नाम पर वोट मांगा था। तेलंगाना की जनता ने विश्वास कर अपना समर्थन उन्हें दिया। लेकिन सत्ता में आते ही कांग्रेस ने जन विश्वास से अन्याय किया। चुनाव से पहले ढेरों वादे करो और सत्ता में आते ही सबको तिलांजलि दे दो, यही कांग्रेसी संस्कृति है। भारतीय जनता पार्टी प्रारंभ से ही तेलंगाना राज्य की पक्षधर रही है। हम छोटे राज्यों के समर्थक है। यदि संसद में तेलंगाना राज्य बनाने का प्रस्ताव आता है तो हम उसका निश्चित रूप से उसका समर्थन करेंगे।

संगठनात्मक चुनाव

आने वाले कुछ माह में संगठनात्मक चुनाव पूरे होंगे। पिछली कार्यसमिति में हमने संगठनात्मक चुनाव की तिथियों संबंधी चर्चा कर चुनावी समयसारिणी भी बनाई थी। हमारा तो एक ही आग्रह है कि संगठनात्मक चुनाव में पारदर्शिता रहे। जो कार्यकर्ता अथक परिश्रम कर पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, उनको उपयुक्त स्थान एवं सम्मान मिलना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि पार्टी में लोकतांत्रिक भावना हमेशा प्रबल रहे।

मैं मानता हूं कि संगठनात्मक चुनाव नियमित होना चाहिए और मंडल ईकाई से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक पार्टी के संविधान के अनुसार सम्पन्न होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि पार्टी कार्यकारिणी में समाज के सभी वर्गों को समुचित स्थान मिले। भाजपा एक संस्कारित और अनुशासित राजनीतिक दल है। हम प्रयास करें कि भाजपा की विशिष्ट पहचान हमेशा कायम रहे।

आगामी विधानसभा चुनाव

संगठनात्मक चुनाव के बाद ही चार महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव संपन्न होने हैं। ये चुनाव राज्य उत्तरप्रदेश, उत्तरांचल, पंजाब एवं मणिपुर में हैं। सभी लोगों को जानकारी होगी ही कि उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पंजाब में हम सरकार में रह चुके हें। संगठनात्मक स्तर पर इन राज्यों में चुनावी व्यवस्थाएं प्रारम्भ हो चुकी हैं। अभी अनेक स्तरों पर तैयारी करनी है। मुझे विश्वास है कि हम सभी लोग प्राण–पण से जुटेंगे तो निश्चित ही चुनावी परिणाम हमारे मनानुकूल होगा।

यूपीए सरकार निरंतर जनविश्वास खो रही है। पर केवल इसी आधार पर सरकार बदलने की स्वाभाविक प्रक्रिया का लाभार्थी मात्र होना हमारा राजनैतिक उद्देश्य नहीं है। हमने एक वैभवशाली राष्ट्र बनाने का व्रत लिया है। हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपनी राजनैतिक विचारधारा का व्याप बढ़ाना ही होगा। यहां मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कार्य सरल नहीं है। यह केवल कागजों पर लिखने से नहीं होगा। यह तभी होगा जब हम अपने राजनैतिक व्याप को बढ़ाने की योजना बनाएंगे। साथ ही उस योजना को साकार करने के लिए सामूहिक रूप से टीम बनाकर इस दिशा में प्रयत्न करें तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। हमें दल के कार्य विस्तार की ओर विशेष ध्यान देना होगा। हम अभी तक जिन क्षेत्रों में नहीं पहुंचे हैं हमें वहां पर अपने कार्य और कार्यक्रमों को कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाना होगा। हमें अपने समर्थक और मतदाता दोनों में वृद्धि करनी होगी। हम सदैव से सकारात्मक राजनीति के पक्षधर रहे हैं। इसका यह अर्थ नहीं है कि हमें जो स्वाभाविक सत्ता विरोधी लाभ मिले, हम उससे वंचित रह जाएं। पर आज हमारे लिए यह महती आवश्यकता है कि हम अपनी विचारधारा और राजनैतिक व्याप बढ़ाने में अपनी सारी शक्ति के साथ लग जाएं। यह केवल भाजपा के राजनैतिक भविष्य के लिए नहीं बल्कि इस महान राष्ट्र के सुरक्षित भविष्य के लिए भी परम आवश्यक है।

––––